

एससीओ में भारत का अकेला पड़ना, विदेश नीति की कमज़ोरी झलकाता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, एससीओ (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) में सदा से भारत को एक महत्वपूर्ण सीट मिलती थी, पर, अब भारत की उपस्थिति मात्र एक औपचारिकता होकर रह गई है

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। हाल ही में संपन्न हुए शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत के कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने की बढ़ती हुई स्थिति ने रणनीतिक विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

यह मंच, जिसे कभी भारत के लिए पूर्व और पश्चिम के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करने के एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता था, अब वैश्विक मंच पर नई दिल्ली के घटते प्रभाव को दर्शाता है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि वर्तमान शासन के तहत लगातार हुई विदेश नीति की गलतियों के कारण भारत की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है और यह स्थिति एससीओ जैसे महत्वपूर्ण

- इस “दयनीय स्थिति” की जिम्मेवारी विदेश मंत्री एस. जयशंकर की “धूल धूसरित” भूमिका को माना जाता है।
- विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना ​​है, विदेश मंत्री सरकार की सोच (आइडियोलॉजी) के प्रवक्ता बनकर रह गए, जबकि उनको भारत के सामरिक हितों का रक्षक बनना था।
- अंतर्राष्ट्रीय फोरम (प्लेटफॉर्म) पर देशभक्ति पूर्ण भाषणबाजी को आक्रामक तरीके से दोहराने से, हालाँकि उनकी देश में लोकप्रियता बढ़ी, पर, इस आक्रामक स्टैंड से विश्व में भारत के प्रतिद्वंद्वियों के मन में कोई सच्ची दोस्ती नहीं बन पाई और न प्रतिद्वंद्वियों के भारत के प्रति रुख में कोई परिवर्तन आया।
- यहाँ तक कि परम्परागत रूप से भारत के समर्थक देश, ईरान व सेंट्रल एशिया के छोटे-छोटे नये देश भी धीरे-धीरे चीन के नज़दीक जाने लगे हैं और भारत के लिए रंगमंच पर भूमिका निभाने के लिए जगह और कम हो गई है।

भू-राजनीतिक मंच पर शर्मनाक हद तक अलग-थलग पड़ जाने के रूप में सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा “पड़ोसी पहले” और “विश्व गुरु” जैसे

नारे देकर प्रभावी कूटनीति की जो शुरुआत की गई थी, उसकी ज़मीनी हकीकत अब एक रणनीतिक शून्य के रूप में सामने आ रही है। अफगानिस्तान, आतंकवाद- निरोध,

क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और संपर्क परियोजनाओं सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चाओं में भारत को स्पष्ट रूप से दरकिनार कर दिया गया। पर्यवेक्षकों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया

नयी दिल्ली, 27 जून। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम के बाद मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्वी से टेलीफोन पर बात की और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

डॉ. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज दोपहर ईरान के

- जयशंकर ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्वी का आभार जताया।

विदेश मंत्री अराग्वी से बात की। वर्तमान जटिल स्थिति में ईरान के दृष्टिकोण और सोच को साझा करने के लिए उनकी सराहना करता हूँ। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए उनका धन्यवाद। ऑपरेशन सिंधु के तहत, अब तक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के साथ-साथ, परस्पर लाभ हेतु अच्छे पड़ोसी संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने 2020 की सीमा झड़प के बाद उत्पन्न हुई विश्वास की कमी को ज़मीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करके दूर करने और पुनः भरोसा बढ़ाने की भी अपील की। अपने रूसी समकक्ष के साथ बैठक में दोनों नेताओं के बीच वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति, सीमा पार के आतंकवाद और भारत-रूस रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। रूसी रक्षा मंत्री ने भारत-रूस के

दीर्घकालिक संबंधों को याद करते हुए कहा कि ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। साथ ही, उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह और कायरतापूर्ण आतंकी हमले को लेकर भारत के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि किंगदोआ में रूस के रक्षामंत्री आन्द्रे बेलोउसोव से मुलाकात कर खुशी हुई। भारत-रूस रक्षा सम्बंधों को मजबूत करने को लेकर उपयोगी विचार- विमर्श हुआ। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापार समझौता कर सकता है अमेरिका’

नई दिल्ली, 27 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ ‘बहुत बड़ा’ व्यापार समझौता कर सकता है। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अंतिम दौर की व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन गया हुआ है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत आयात शुल्क

- अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि हम भारत के साथ भी वैसा ही समझौता करेंगे, जैसा चीन के साथ किया है।

लगाया था, लेकिन भारत सरकार के रूख को देखते हुए उसे नौ जुलाई तक स्थगित कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गयी। वाइट हाउस में एक कार्यक्रम में ट्रम्प ने कहा कि चीन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और भारत के साथ भी इसी तरह का व्यापार समझौता हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा, हम के साथ एक समझौता हो सकता है...हम भारत के साथ उसी तरह का समझौता करने जा रहे हैं, जैसा चीन के साथ किया है।

‘केवल भाषणबाजी, इच्छाशक्ति व व्यक्तिगत “डिप्लोमैसी” से युद्ध समाप्त नहीं होते’

“हेग” (नीदरलैण्ड) में आयोजित नाटो के शिखर सम्मेलन में ट्रंप की स्वीकारोक्ति से काफी चिंतित हुए दर्शक

- इस सम्मेलन में ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा था कि वे “मिसगाइडेड” हैं तथा क्रैमलिन की कोई रूचि नहीं कि युद्ध समाप्त हो।
- ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन में यह भी कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलेंस्की की जिद, कि युद्ध के बारे में “नैतिक कंप्यूजन” पहले साफ होना चाहिए, के नारे के कारण भी यूक्रेन युद्ध समाप्त होने में विलम्ब हो रहा है।
- ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन का युद्ध केवल एक रात में ही खत्म नहीं हो जायेगा। उन्होंने यह बात भी कही कि अगर, रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगाये गये तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। पुतिन का रुख और कड़ा व सख्त ही होगा।

कोई रूचि नहीं है।” यह एक चौकाने वाली स्वीकारोक्ति थी, विशेषकर इसलिए कि ट्रंप को कभी माँस्को के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। उन्होंने यह भी माना कि यह युद्ध खुद रूस के लिए भी “एक बड़ी मुसीबत” बन गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी ठोस प्रगति की उम्मीद अब भी क्षीण है। साथ ही, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ैलेंस्की को ओर भी एक

जटिल कारक के रूप में इंगित किया। यद्यपि उन्होंने सीधी आलोचना से परहेज़ किया, पर यह संकेत दिया कि ज़ैलेंस्की का राजनैतिक रुख, जिसमें नैतिक स्पष्टीकरण पर जोर देना, पश्चिमी एकजुटता की मांग और आभार की अपेक्षाएं शामिल हैं, परदे के पीछे की कूटनीति में बाधा बना है। ट्रंप ने ज़ैलेंस्की के साथ अपनी मुलाकात को “लंबी और सार्थक” बताया, लेकिन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन, अमेरिका को “रेअर अर्थ” खनिज निर्यात करने पर राजी हुआ

अमेरिका ने “रेअर अर्थ” का निर्यात खुलवाने के लिए साम-दाम-दण्ड-भेद सहित सभी तरीके अपनाये

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। हर कोई शक्ति के प्रभाव को समझता है, और सबसे अधिक, चीना चीन ने जहाँ दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) के अमेरिका को निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति दे दी है, वहीं, चीन, भारत के लिए ऐसे ही निर्यातों को लगतार सीमित कर रहा है।

व्यापार, आर्थिक मुद्दे और भू-राजनीति (जिओपॉलिटिक्स) आज की बदलती वैश्विक कूटनीति में गहराई से उलझते जा रहे हैं। ऐसे में अब यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि आर्थिक नीतियों को भू-राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप ढाला जाए।

एक विजय की घोषणा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति और वाणिज्य सचिव ने गुस्वार को कहा था कि चीन अमेरिका को इन वस्तुओं का निर्यात फिर से शुरू करेगा। अगले ही दिन चीन ने भी यही घोषणा की। अमेरिका और

- पर, अमेरिका को कामयाबी तब मिली, जब उसने अमेरिका में पढ़ रहे सभी चीनी विद्यार्थियों के वीजा कैन्सल करने की धमकी दी।
- तथापि, चीन ने अभी भी भारत के लिए “रेअर अर्थ” की सप्लाई नहीं खोती है।
- चीन की दृष्टि से भारत एक बड़ा मार्केट है, अतः भारत की “मैन्यूफैक्चरिंग” को बढ़ाने में चीन कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है।
- भारत भी अपनी तरफ से चीन के निर्यात को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, चीन के भारत में “इन्वेस्टमेंट” के प्रस्तावों पर भारत सरकार बड़ी बारीकी से निरीक्षण करती है और बड़े ही बेमन से एकाध प्रस्ताव को ही स्वीकार करती है।

चीन दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर सहमत हो गए हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और डिफेंस सैक्टर एप्लिकेशन के लिए बेहद जरूरी कच्चा माल हैं। अमेरिकी

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने तीखे शब्दों में कहा था कि चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिजों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। दोनों देशों के बीच चल रही दबाव की राजनीति का अंदाज़ा इस बात से लगाया

जा सकता है कि पिछले सप्ताह अमेरिका ने इथेन व्यापारियों को चीन जाने वाले जहाजों पर माल लाने की अनुमति तो दी, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बिना चीन में माल उतारने पर प्रतिबंध लगा दिया।

दुर्लभ खनिजों और मैनेटेन्स के निर्यात पर यह सहमति, लंबे समय से चल रही बातचीत, धमकियों (जैसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक चिपस और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति रोकने की चेतावनी) का परिणाम है। तथापि, अमेरिकी प्रशासन ने अपनी बात मनवाने के लिए कई धमकियाँ दीं। इनमें से एक धमकी यह थी कि अमेरिका के अग्रणी विश्वविद्यालयों में दाखिल चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। इस एक धमकी ने चीन को बुरी तरह झकझोर दिया और खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसकी निंदा करनी पड़ी। पूरे चीन में, अमेरिका के इन विश्वविद्यालयों में दाखिला पाना एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित ?

तेहरान, 27 जून। ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को 22 जून के अमेरिकी हवाई हमलों से पहले फोर्डो केन्द्र से स्थानांतरित कर दिया था। यह जानकारी फाइनैशियल टाइम्स ने

- फाइनैशियल टाइम्स ने यूरोपीय अधिकारियों के खुफिया आंकलन के आधार पर दावा किया कि फोर्डो में संवर्धित 60 प्रतिशत शुद्धता वाला 408 किलो यूरेनियम अलग-अलग जगहों पर रखा गया था।

शुक्रवार को यूरोपीय अधिकारियों द्वारा साझा किए गए प्रारंभिक खुफिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नए डीजीपी के लिए यूपीएससी ने तीन नामों का पैनल भेजा है

ये तीनों वरिष्ठतम अधिकारी हैं, राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल

जयपुर, 27 जून। राजस्थान पुलिस को जल्दी ही नया पुलिस महानिदेशक मिलने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने राज्य सरकार को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा है। ये तीन अफसर हैं - राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनमें से किसी एक को चुनकर नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेंगे। पुलिस विभाग और प्रशासनिक गलियारों में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह और उत्सुकता का माहौल है। जानकारी के अनुसार, यूपीएससी ने नियमों के अनुसार यह पैनल तैयार किया है। इसमें अधिकारियों की वरिष्ठता,सेवा रिकॉर्ड और केन्द्र और राज्य स्तर पर अनुभव को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही नए पुलिस



राजेश निर्वाण

महानिदेशक की नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं। यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है, क्योंकि वर्तमान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा तीस जून 2025 को



संजय अग्रवाल

सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गौरतलब है कि पैनल में शामिल तीनों अधिकारी अनुभवी और कबिल हैं और वरिष्ठता को पैमाना माना जाए तो राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल में से किसी एक को



राजीव शर्मा

राजस्थान पुलिस की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन अगर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई तो किसी अन्य अधिकारी को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह फैसला मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर

- यूपीएससी ने पैनल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है, अगर वरिष्ठता को आधार माना गया तो इन तीनों में से किसी एक को राजस्थान पुलिस का मुखिया बनाया जाएगा।
- लेकिन अगर वरिष्ठता को आधार नहीं माना गया तो किसी अन्य को भी यह पद मिल सकता है, फिलहाल पुलिस विभाग सहित समूचे प्रशासन में इस नियुक्ति को लेकर भारी उत्सुकता का माहौल है।
- कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा सोमवार 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। माना जा रहा है कि तब तक नए डीजीपी के नाम का फैसला हो जाएगा।

करेगा। नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर पुलिस विभाग से लेकर प्रशासन तक चर्चाओं का माहौल गर्म है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की बागडोर किसके हाथों में दी जाएगी। यह नियुक्ति न केवल

पुलिस बल के लिए, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस को नया नेतृत्व मिलेगा, जो प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

एसीबी के एडिशनल एसपी की गाड़ी से 9.35 लाख रुपए बरामद

जयपुर, 27 जून। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर शुक्रवार देर रात को एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा की गाड़ी का अचानक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गाड़ी में 9 लाख 35 हजार रुपए मिले। एसीबी के

- मुख्यालय के निर्देश पर एडिशनल एसपी जगराम मीणा की गाड़ी का अचानक निरीक्षण किया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ और स्पेशल यूनिट द्वितीय के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया, एसीबी की टीम द्वारा जगराम मीणा की कार का झालावाड़ से जयपुर आते हुए शिवदासपुरा टोल पर अचानक निरीक्षण किया गया।